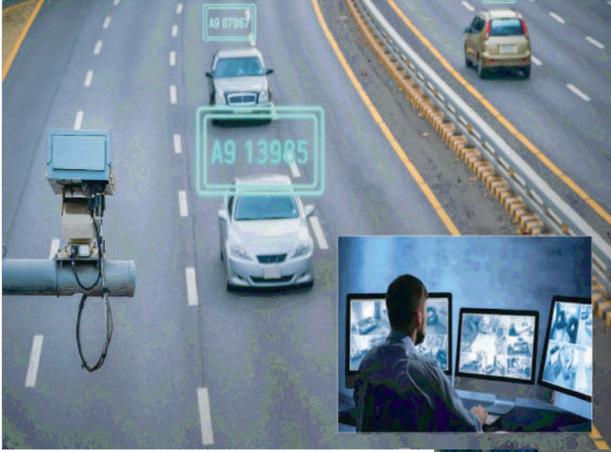


03 सिंधी रॉयल क्लब सिंधी चेटी चंड मेला का पंजाबी बाग में करेगा आयोजन

06 बच्चे बचपन में अपनी माँ से बहुत कुछ सीखते हैं। विजय गर्ग

08 मारवाड़ी युवा मंच सिकंदराबाद शाखा द्वारा रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया

नंबर प्लेट पढ़कर एआइ कैमरे देंगे उम्र पूरी कर चुके वाहन की जानकारी....



संजय बाटला

दिल्ली सरकार अब पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं देने जा रही है। पेट्रोल पंपों पर लगे एआइ कैमरों की मदद से वाहनों की आयु की पहचान की जाएगी और अगर वाहन पुराना है तो उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था 15 से 20 अप्रैल के बीच शुरू होने की उम्मीद है। इनमें 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार पेट्रोल पंपों पर ऐसी व्यवस्था स्थापित करने जा रही है कि ऐसे वाहन जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। वहां लगे एआइ कैमरों की मदद से वाहनों की आयु की पहचान की जाएगी। इसका मतलब यह है कि पेट्रोल पंप पर

मौजूद कर्मचारियों समेत सभी को यह जानकारी मिल जाएगी कि वहां कोई पुराना वाहन आया है। अगर वाहन पुराना है तो लाउडस्पीकर पर घोषणा होने पर वाहन मालिकों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। यह सुविधा पहले एक अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन तैयारियां पूरी न होने के कारण अब इसके 15 से 20 अप्रैल के बीच शुरू होने की उम्मीद है।

इस तरह कैमरे से होगी पहचान ये एआइ कैमरे वाहन पोर्टल से जुड़े रहेंगे। ये वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र, वाहन पुराना है या नहीं और इंश्योरेंस की भी जानकारी देंगे। प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि ट्रायल के तौर पर कुछ पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने का मैसेज भेजने की व्यवस्था शुरू की

गई है, जो सफल रही है।

सूत्रों ने बताया कि पहले कहा जा रहा था कि दो घंटे की चेतावनी के बाद पेट्रोल पंपों पर पहुंचने वाले बिना पीयूसीसी वाले वाहनों का 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा, लेकिन नई सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

इस सिस्टम के तहत पेट्रोल पंपों पर लगाए जा रहे स्पीकर ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट करके अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों की जानकारी देंगे। सिस्टम के तहत एआइ कैमरा वाहन के पुराने होने के बारे में अलर्ट देगा जो पेट्रोल पंप के डैशबोर्ड पर फ्लैश होगा और फिर स्पीकर वाहन की उम्र बताने की घोषणा करने लगेगा।

वाहन की उम्र पूरी होने की पता लगाएगी सिस्टम दरअसल, ये एआइ कैमरे सरकार के

वाहन पोर्टल से जुड़े होंगे, जिसके जरिए सिस्टम वाहन की उम्र पूरी होने की जानकारी हासिल कर सकेगा।

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में मौजूद लगभग सभी 400 पेट्रोल पंपों पर यह व्यवस्था की जा रही है। पिछले साल तक दिल्ली में 59 लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है। इनमें 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं।

इनमें से कितने वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। लेकिन, कुछ वाहन स्कैप हो चुके हैं और कुछ ने एनओसी लेकर दूसरे राज्यों में अपने वाहनों का पंजीकरण करा लिया है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निरञ्जल सिंघानिया ने कहा कि दिल्ली के पेट्रोल पंप मालिक प्रदूषण रोकने में सरकार के साथ हैं।

पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है



जीवन आनन्द के लिए है, चाहे जो हो, बस मुस्कुराते रहो। यदि आप चिंतित हो, तो खुद को थोड़ा आराम दो, हो सके तो जरूरत मंदो की सहायता करो। यह अंग्रेजी वर्ण, हमें सिखाते हैं :-

A B C ?
Avoid Boring Company .
मायूस संगत से, दूरी बनाए रखना।
_ D E F...?
Dont Entertain Fools .
मूर्खों पर, समय व्यर्थ मत करो।
_ G H I...?
Go For High Ideas .
ऊँचे विचार रखो।
_ J K L M...?
Just Keep A Friend Like Me .
मेरे जैसा, मित्र रखो।
_ N O P...?
Never Overlook The Poor n Suffering .
गरीब व पीड़ित को ,कभी भी, अनदेखा मत करो!
Q R S...?
Quit Reacting To Silly Tales .
मूर्खों को , भूलकर भी प्रतिक्रिया मत दो !
T U V...?
Tune Urself For Ur Victory .

खुद की जीत, सुनिश्चित करो!
W X Y Z...?
We Xpect You To Zoom Ahead In Life
इसलिये, हम आपसे, जीवन में, आगे देखने की, आशा करते हैं।

1. यदि आपने चाँद को देखा, तो आपने ईश्वर की सुन्दरता देखी!
2. यदि आपने सूर्य को देखा, तो आपने ईश्वर का बल देखा!
3. और यदि आपने आईना देखा, तो आपने ईश्वर की, सबसे सुंदर रचना देखी!
इसलिए, स्वयं पर विश्वास रखो . जीवन में हमारा उद्देश्य होना चाहिए :-
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
9 - गिलास पानी
8 - घण्टे नींद
7 - यात्रियों परिवार के साथ
6 - अंकों की आय
5 - दिन हपते में काम
4 - चक्का वाहन
3 - बेडरूम वाला पलैट
2 - अच्छे बच्चे।
1 - जीवन साथी
0 - चिन्ता ...?

- संजय बाटला

देश की पहली तीन कोच की मेट्रो दिल्ली में, क्या होगा रूट और कितने होंगे स्टेशन...

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) का लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक रूट पर तीन कोच वाली ट्रेन चलेगी। यह कॉरिडोर आठ किलोमीटर लंबा होगा। यह देश में पहली तीन कोच वाली मेट्रो लाइन होगी और इसके प्लेटफार्म भी छोटे होंगे। इसमें लगभग 80 हजार लोग रोजाना सफर कर सकेंगे। आइए जानते हैं इस कॉरिडोर पर कौन से 8 स्टेशन होंगे और उसके क्या फायदे होंगे।

नई दिल्ली। फेज चार की लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक मेट्रो लाइन देश की पहली ऐसी मेट्रो लाइन होगी जिस पर तीन कोच की मेट्रो ट्रेनें चलेगी। इस कॉरिडोर पर पहला और आखिरी दोनों स्टेशन वर्तमान दो इंटरचेंज स्टेशन से जुड़े होंगे और कॉरिडोर लाजपत नगर मार्केट व सलेक्ट सिटी वाँक मॉल को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा।

कितनी होगी मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई? दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) का कहना है कि व्यस्त समय में इस कॉरिडोर पर जितने यात्रियों के सफर करने का अनुमान है उसे

तीन कोच की मेट्रो से आसानी से पूरा किया जा सकता है।

करीब आठ किलोमीटर लंबे इस एलिक्ट्रिक मेट्रो कॉरिडोर पर आठ स्टेशन होंगे। यह वर्तमान ग्रे लाइन (द्वारका-हांसा बस स्टैंड) दिल्ली मेट्रो का दूसरा सबसे छोटा कॉरिडोर होगा।

इन स्टेशनों के प्लेटफार्म सामान्य मेट्रो स्टेशनों की तुलना में छोटे होंगे। देश में चार, छह व आठ कोच की मेट्रो का परिचालन हो रहा है। स्टैंडर्ड गेज के वर्तमान कॉरिडोर के मेट्रो स्टेशनों के प्लेटफार्म की लंबाई सामान्य तौर पर 140 मीटर है। स्टैंडर्ड गेज के कॉरिडोर पर अभी छह कोच की मेट्रो का परिचालन हो रहा है।

कब से शुरू होगा काम? वहीं लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर के प्लेटफार्म की लंबाई 74 मीटर होगी। डीएमआरसी ने इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए जनवरी में टेंडर प्रक्रिया शुरू थी।

टेंडर आवंटन के बाद जल्द ही इसका निर्माण शुरू हो जाएगा और करीब तीन वर्ष में बनकर तैयार होगा। प्लेटफार्म छोटे व तीन कोच की मेट्रो



का परिचालन होने से इस कॉरिडोर के निर्माण व संचालन शुरू करने में लागत कम आएगी।



सुविधा? योजना के अनुसार यह कॉरिडोर वर्ष 2025 से पहले बनकर तैयार होनी थी, लेकिन इस

कॉरिडोर को पिछले वर्ष ही निर्माण के लिए सरकार से स्वीकृति मिली। यदि यह कॉरिडोर बनकर अब तक तैयार हुआ होता तो इस वर्ष प्रतिदिन 60,000-80,000 यात्रियों के सफर करने का अनुमान था।

इस कॉरिडोर पर होंगे ये स्टेशन और उसके फायदे

लाजपत नगर - पिक और वायलेट लाइनों के साथ इंटरचेंज, लाजपत नगर मार्केट जुड़ने वाला यह तीसरा कॉरिडोर होगा।
एंड्रयूज गंज - आवासीय और संस्थागत इलाके को फायदा।
ग्रेटर कैलाश एक - ग्रेटर कैलाश और आसपास के इलाकों की सेवा।
चिराग दिल्ली - मैजेटा लाइन के साथ इंटरचेंज।
पुष्पा भवन - सरकारी कार्यालयों और आवासीय कॉलोनिजों मेट्रो से जुड़ेगी।
साकेत कोर्ट - साकेत जिला न्यायालय परिसर, सलेक्ट सिटी वाँक मॉल पहुंचा जा सकेगा।

पुष्प विहार - पुष्प विहार सेक्टर एक, तीन, चार और सात के निवासियों को फायदा।

साकेत जी ब्लॉक - गोलडन लाइन (तुगलकाबाद-एरोसिटी) के साथ इंटरचेंज स्टेशन। इस स्टेशन पर मेट्रो बदलकर पहुंचा जा सकेगा एयरपोर्ट।

मेट्रो के एक कोच में कितने यात्री करेंगे सफर?

वर्ष 2041 तक इस कॉरिडोर की मेट्रो में प्रतिदिन करीब एक लाख 20 हजार यात्रियों के सफर करने का अनुमान है। मेट्रो ट्रेन के एक कोच में 300 यात्री सफर कर सकेंगे। इस लिहाज से तीन कोच की मेट्रो में एक बार में करीब 900 यात्री सफर करेंगे। यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ मेट्रो की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी। डीएमआरसी का कहना है कि इस कॉरिडोर पर तीन कोच के मेट्रो का परिचालन होने से बिजली की खपत भी कम होगी और पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगा। यह कॉरिडोर बनकर तैयार होने पर दक्षिण और मध्य दिल्ली के बीच मेट्रो से आवागमन की सुविधा बेहतर होगी।

टैपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathiasanjanjaybathia@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

अब वन टाइम पेमेंट के साथ पाएं नमो भारत और दिल्ली मेट्रो के यात्रियों की सबसे बड़ी टेंशन खत्म

परिवहन विशेष न्यून नमो भारत कनेक्ट एप में अब यात्रा की संयुक्त योजना बनाने का फीचर शुरू हो गया है। इस फीचर से यात्री एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नमो भारत ट्रेन और मेट्रो ट्रेन की टिकट अलग-अलग ले सकते हैं। यात्री चाहें तो एक भुगतान पर नमो भारत और मेट्रो ट्रेन का अलग-अलग क्यूआर कोड आधारित टिकट उनको मिल जाएगा।

दिल्ली। नमो भारत ट्रेन और मेट्रो ट्रेन रूट पर यात्रा की संयुक्त योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने नमो भारत कनेक्ट एप में जर्नी प्लानर की शुरुआत की है।

इस फीचर के साथ यात्री एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक भुगतान पर दोनों की ट्रेन माध्यमों की टिकट अलग-अलग टिकट ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी को मेट्रो साउथ से दिल्ली

के राजीव चौक तक जाना है, तो एप के जर्नी प्लानर फीचर में यात्री को शुरुआती और गंतव्य स्टेशन का नाम डालना होगा। यात्रियों के लिए शुरू हुई ये सुविधा

ऐसा करने पर एप बता देगी कि आपको नमो भारत ट्रेन से आनंद विहार उतरना होगा, वहां से मेट्रो की ब्लू लाइन पकड़ कर आप राजीव चौक पहुंच जायेंगे। यात्री चाहें तो एक भुगतान पर नमो भारत और मेट्रो ट्रेन का अलग-अलग क्यूआर कोड आधारित टिकट उनको मिल जाएगा। अभी तक टिकट खरीदने के लिए भुगतान भी अलग-अलग करना होता था। यात्रा की योजना बनाने के लिए रूट भी अलग-अलग देखा जाता था।

एनसीआरटीसी अधिकारियों ने बताया कि यह फीचर एक स्टेशन से दूसरे के बीच के यात्रा के लिए स्मार्ट रूट का सुझाव देता है। यात्री इससे सबसे तेज और सबसे कुशल रूट की जानकारी लेने के साथ-साथ अनुमानित यात्रा समय और सुझाए गए इंटरचेंज भी देख सकते हैं।



भुगतान के लिए दिए ऑफ़ान इस फीचर से एक ही प्लेटफॉर्म पर नमो भारत और मेट्रो दोनों के टिकट एक साथ बुक करने की सुविधा है। इससे यात्रियों को दो अलग-अलग एप पर जाकर दोनों माध्यमों के लिए अलग-अलग टिकट बुक करने की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। नमो भारत एप पर ही पूरी यात्रा का अनुमानित किराया देखकर यूपीआइ, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान कर सकते हैं।

संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है!

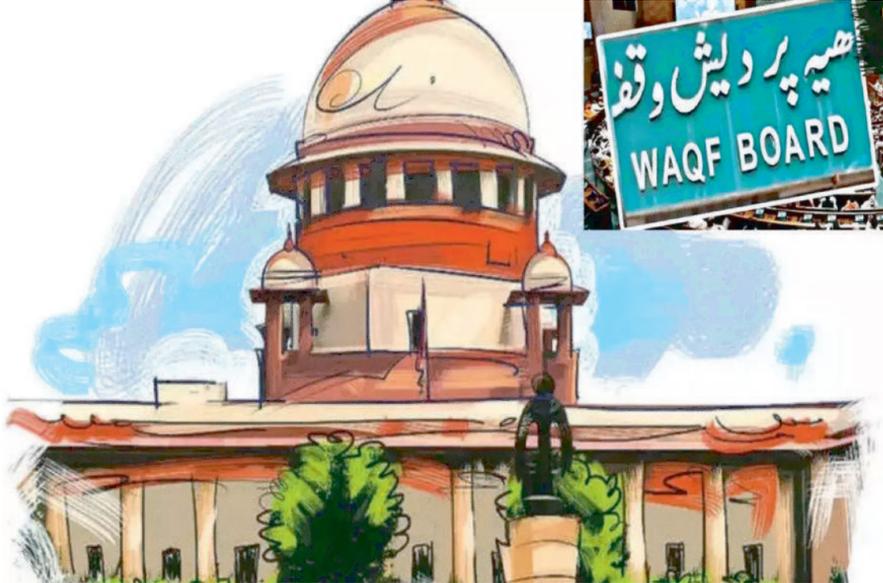
रामस्वरूप रावतसरे

वक्फ संशोधन बिल आखिरकार जोरदार हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत के साथ पारित हो गया है। इसे लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने विरोध जताया था मगर सरकार ने सदनों में चर्चा करने के बाद इस पर वोटिंग करा ली, जिसमें यह कानून पास हो गया। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पेलान किया है कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस बिल की वैधता को चुनौती देगी। कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चुनौती देने की बात कही है। अब सवाल उठता है कि क्या संसद के बनाए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। क्या न्यायपालिका संसद के बनाए कानून को रद्द कर सकती है?

कानून के जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऐसे में वह यह सुनिश्चित करने के लिए संसद के बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है कि वे संविधान के अनुरूप हों। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ है, तो वह उसे रद्द कर सकता है। हालांकि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। आमतौर पर संसद से किसी भी पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता है।

कानून के जानकारों का यह भी कहना है कि संविधान के अनुसार, संसद केवल संविधान को बदलने या संविधान में संशोधन करने के लिए उत्तरदायी है। संसद के पास केवल नए कानूनों का पारित करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। ऐसे में संसद के अलावा किसी भी संस्था या व्यक्ति को किसी पारित कानून को रद्द करने का अधिकार नहीं है। संविधान के जरिए स्थापित संस्थाओं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के पास केवल विशेष विधि और न्याय अधिकार होते हैं जो कि उन्हें किसी कानून को रद्द करने का अधिकार देते हैं।

कानून विशेषज्ञों के अनुसार संसद सभी विषयों पर कानून बना सकती है मगर वह संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 (1) संसद को संविधान में निधारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़कर, बदलकर या हटाकर संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है।



1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारतीय मामले में संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर व्यापक रूप से चर्चा हुई। इसमें यह निष्कर्ष निकला कि एक संवैधानिक संशोधन भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता है। बुनियादी संरचना सिद्धांत का मानना है कि भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान को संशोधित करने या समाप्त करने का अधिकार नहीं है। कानून के तहत व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा इस सिद्धांत के अभिन्न अंगों में से एक है।

भारतीय संविधान का भाग 1।। (अनुच्छेद 12-35) कुछ स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। वहीं, अनुच्छेद 13 किसी भी नए कानून को लागू करने पर रोक लगाता है जो इन स्वतंत्रताओं का उल्लंघन कर सकता है। यह प्रावधान न्यायालयों को संविधान के अनुसमर्थन से पहले और बाद में बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता का पता लगाने का अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस, परमादेश, उल्फेण और क्वो वारंटो जैसे रिट जारी कर सकता है। विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायपालिका का अधिकार संविधान के शक्तियों के पृथक्करण के प्रावधान को कायम रखता है।

इस संबंध में कानून विशेषज्ञ अनिल सिंह के अनुसार फरवरी, 2023 में एक मामले की

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- कानून बनाता संसद की संप्रभुता है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। इस टिप्पणी के साथ शीष अदालत ने एक उम्मीदवार को दो विधानसभा या संसदीय क्षेत्र से एकसाथ चुनाव लड़ने से रोकने की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में वक्फ संशोधन विधेयक के मामले में अगर चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा ही कह सकता है। उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला को पीठ ने कहा कि कई कारणों से उम्मीदवार अलग-अलग सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। यह संसद की संप्रभुता के दायरे में आने वाली विधायी नीति का प्रश्न है। आखिर यह संसद की इच्छा है कि राजनीतिक लोकतंत्र को इस तरह का विकल्प देकर आगे बढ़ाया जाए या नहीं। उसे ही तय करने दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में इन संवैधानिक आधार पर विषय चुनौती दे सकता है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 25 भारतीय नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संपत्ति और संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। ऐसे में अगर वक्फ संपत्तियों का प्रशासन बदलता है या इसमें गैर-मुस्लिमों को शामिल किया जाता है, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का

उल्लंघन हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन का उल्लंघन। यह अनुच्छेद धार्मिक समुदायों को अपनी धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधित करने का अधिकार देता है। इस विधेयक से वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कमी आ सकती है जिससे यह प्रावधान प्रभावित हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 यानी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का उल्लंघन। मुस्लिम संगठनों का दावा है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों को कमजोर कर सकता है और उनकी संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में ले सकता है।

कानून विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कई बार संसदीय कानूनों को कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा था। अनुच्छेद-370 को केंद्र सरकार ने 2019 में निरस्त कर दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ऐसे में ज्यादा संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ विधेयक को रद्द कर सकता है। वही नहीं करे, वह ज्यादा से ज्यादा यह देख सकता है कि वक्फ का मसला धार्मिक मामले से जुड़ा है या नहीं और यह संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता है।

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है: उपेंद्र सिंह

आगरा,संजय सागर सिंह।पूज्य डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिवस संविधान पर वरिष्ठ भाजपा नेता उपेंद्र सिंह ने डॉ. अंबेडकर जी के बलिदान एवं योगदान और उनके विचारों पर प्रकाश डाला और कहा कि डॉ. अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के निर्माण के साथ-साथ समाज में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ भी संघर्ष किया। उनका जीवन शोधित, वचितों, और महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पित था। डॉ. अंबेडकर जी का दृष्टिकोण यह था कि समाज में आर्थिक समाजिक समानता और स्वतंत्रता होनी चाहिए, और इसके लिए नैतिक शिक्षा और वैचारिक संघर्ष की आवश्यकता है। उनका प्रसिद्ध उद्देश्य रक्षित बनो, राष्ट्रहित में संगठित रहो, वैचारिक संघर्ष करो। आज भी

युवाओं को प्रेरित करता है। श्री सिंह ने डॉ. बाबा साहेब के संविधान को सुरक्षा कवच बताते हुए कहा कि यह हम सभी के लिए न्याय, एकता, और आर्थिक सामाजिक समानता के अधिकार की गारंटी है। उन्होंने संविधान दिए कर्तव्यों और अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया और यह भी बताया कि संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह देशहित में, नैतिक और मौलिक अधिकारों का स्रोत है। डॉ. बाबा साहेब मानते थे कि राष्ट्रहित में सर्व समाज की एकता को मजबूत किया जाना चाहिए और हर व्यक्ति को समाज में समान आर्थिक एवं सामाजिक सम्मान और अधिकार मिलने चाहिए। वरिष्ठ भाजपा नेता उपेंद्र सिंह ने डॉ. अंबेडकर के योगदान और

बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य समाज में आर्थिक एवं सामाजिक असमानता और अशिक्षा को समाप्त करना था, और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर भी विशेष ध्यान दिया। वे चाहते थे कि हर नागरिक को समान अधिकार मिलें और यही उनके जीवन का उद्देश्य था। राष्ट्रहित में, उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से न केवल दलितों बल्कि सभी वर्गों को सम्मान और अधिकार देने की महत्वपूर्ण बात की है। आखिरकार, वरिष्ठ भाजपा नेता उपेंद्र सिंह ने कहा कि डॉ. अंबेडकर जी के बताए रास्ते पर चलकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है, और हम सभी को उनके विचारों को आत्मसात कर संविधान में दिए कर्तव्यों और अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पित होना चाहिए।

कानपुर में 30 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक, ड्राइवर की जलकर मौत

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां जिले में तेज रफ्तार से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके क्रम में बिधुन में एक दर्दनाक सड़क हादसे में डंपर चालक की जलकर मौत हो गई। बीती देर रात यह हादसा शंभुआ दक्षिणांचल विद्युत उपकेंद्र के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक हमीरपुर से लखनऊ जा रहे मौरंग लदे डंपर के चालक श्यामजी द्विवेदी (35) की दुर्घटना में मौत हो गई। रात करीब 2 बजे डंपर अनियंत्रित होकर पहले पेड़ से टकराया। फिर 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस दौरान डंपर की केबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई जिसमें उन्नाव के हसनगंज मुहान ग्राम पिलखना के रहने वाले चालक श्यामजी की मौत हो गई। इस बीच सूचना मिलने पर घाटमपुर से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। बिधुन थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, सोमवार सुबह चालक के शव के अवशेष बाहर निकाले गए। केबिन में सीट के नीचे मिले मोबाइल फोन से चालक की पहचान की गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

रिशतों की चिता ..

कभी एक आँगन था... जहाँ माँ की साड़ी की ओट में दुनिया छुप जाया करती थी। अब उसी आँगन में... "सीमा रेखा" खींची गई है... जमीनी नक्शे से रिशतों का नापा जा रहा है!

कभी जो थाली में एक साथ खाते थे— अब "हिस्से" गिने जाते हैं... और थाली से ज्यादा "बयान" महत्वपूर्ण हो गए हैं। भाई नहीं बोलते अब— वो वकील से बात करते हैं।

माँ की रुलाई अब दीवार के उस पार नहीं सुनाई देती, क्योंकि कानों पर कानूनी हेडफोन चढ़ा है... और दिल... दिल तो अब स्टाम्प पेपर से ज्यादा मुलायम नहीं रहा।

जायदाद क्या बाँटी यारों... बँट तो हम गए थे उस दिन, जब पहली बार "मेरा" और "तेरा" घर के भीतर बोला गया था। वो पहला शब्द ही अंतिम वार था — भाईचारे पर।

कभी जिस जमीन पर हमारे पाँवों के निशान थे, अब उस पर जूते चलते हैं... और दस्तखतों से तय होता है, कौन किसका, कितना अपना है।

अब भी अगर पूछो — रक्वा मिला इस जायदाद से? तो जवाब बस इतना है: रफक दीवार, चार हिस्से, और अनगिनत रिशतों की चिता... र

जायदाद कहाँ बँटी थी... जायदादों में बँट गए भाई। -प्रियंका सोरभ

मैं विषयान करता हूँ

हर मुस्कान के पीछे, छिपा होता है एक चीखता हुआ सच। हर शब्द जो तुम पढ़ते हो, वो मैंने ऑसुओं से लिखा है — स्याही से नहीं।

मैं रोज अपने ही अंदर उतरता हूँ, जहाँ उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, और फिर वहाँ से निकलता हूँ, एक टुकड़ा कविता का — जिसे मैं 'रचना' कहते हो।

ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई सजावटी गुलदान नहीं, ये वो कौटो है जो मैंने हर दिन सीने में चुभोया है — सिर्फ इसलिए कि तुम समझ सको कि दर्द भी सुंदर हो सकता है।

मैं पुरस्कारों के लिए नहीं लिखता, मंच की तालियों के लिए नहीं। मैं लिखता हूँ क्योंकि नहीं लिखूँ तो मर जाऊँ। क्योंकि लिखना — मेरे विषयान का प्रतिकार है। -डॉ. सत्यवान सोरभ

भारत ने विभिन्न देशों से मुक्त व्यापार समझौते करने में बढ़ाई दिलचस्पी

कमलेश पांडेय

भारत ने दो देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते करने में दिलचस्पी दिखाई है ताकि उसके कारोबारियों को भी द्विपक्षीय व्यापार के फायदे मिल सकें। जानकारों का कहना है कि भारत अमेरिका समेत ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ओमान, कतर, न्यूजीलैंड, पेरू, श्रीलंका आदि देशों के साथ मुक्त व्यापार और द्विपक्षीय कारोबार समझौतों पर वार्ता कर रहा है जो यदि सफल हुआ तो इससे हासिल नए बाजार में भारत के छोटे उद्योगों को लगभग डेढ़ दर्जन से ज्यादा कारर मिलेंगे। कमझा जाता है कि इससे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाये गए जवाबी आयात शुल्क भी बेअसर हो जाएंगे।

इस बारे में आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि यदि लांजित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को करने में भारत सफल हो जाता है तो न केवल सीमा शुल्क में कमी आएगी बल्कि उन्हें खत्म भी किया जा सकता है। इससे वहाँ के बाजारों तक भारतीय मालों की पहुंच भी आसान हो जाएगी। इसके अलावा सम्बन्धित देशों के बीच व्यापार की गति तेज होगी और वहाँ होने वाले निवेश की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। साथ ही, बौद्धिक संपदा की रक्षा संभव हो सकेगी। विभिन्न सेवाओं का व्यापार भी बढ़ेगा। इससे जहां उन देशों के साथ लांजिस्टिक लागत कम आएगी, वहीं छोटे व्यवसायों को बम्पर मौके मिलेंगे।

यही वजह है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए जवाबी टैरिफ यानी आयात शुल्क के बीच भारत ने दुनिया के बाकी देशों के साथ जारी व्यापार समझौतों की गति तेज कर दी है। बहरहाल भारत सरकार की कोशिश है कि न केवल अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौता तेजी से पूरा हो बल्कि यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, ओमान, ब्रिटेन जैसे अन्य देशों के साथ भी मुक्त व्यापार (एफटीए) और द्विपक्षीय समझौतों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके दृष्टिगत भारत सरकार ने अपनी ओर से तत्परता बढ़ा दी है ताकि भारतीय मालों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 26 प्रतिशत आयात शुल्क (अमेरिकी रैसिप्रोकल टैक्स) का न्यूनतम असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े। समझा जाता है कि भारत सरकार को इस विषयक

सफलता से भारत के उद्यमियों को अन्य देशों के साथ मिलकर कारोबार करने का मौका मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि मौजूदा वक्त में अमेरिकी व्यापार नीतियों के परिवर्तित स्वरूप को देखते हुए अन्य देशों ने भी भारत के साथ चल रहे व्यापार समझौतों को लेकर जारी वार्ता में तेजी लाने की इच्छा जताई है जिसे भारतीय प्रशासन ने भी हरी झंडी दे दी है। उल्लेखनीय है कि फिलवक्त भारत द्वारा न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ (ईयू), ओमान, पेरू, कतर, और श्रीलंका जैसे 20 से अधिक देशों के साथ भी व्यापार समझौतों पर वार्ता की जा रही है जिसके सार्थक परिणाम शीघ्र मिलने की उम्मीद है। इनमें अमेरिका, कतर, ओमान, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ जारी वार्ता को अच्छी खासी प्राथमिकता दी जा रही है ताकि इसके सार्थक परिणाम भी बहुत जल्द ही सामने आएँ। वहीं, इस बात के प्रबल आसार हैं कि जल्द से जल्द ही इन समझौतों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा क्योंकि अब इन्हीं के जरिए भारत बाकी देशों के साथ मिलकर व्यापार के नए अवसर तलाशने की कोशिश कर रहा है। जानकार बताते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया समेत 13 देशों से इस बाबत पहले ही समझौते कर चुका है। भारत ने विभिन्न देशों/क्षेत्रों अर्थात् जापान, दक्षिण कोरिया, आसियान क्षेत्र के देशों और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया के साथ 13 क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए)/मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि इनकारों का कहना है कि व्यापार समझौतों के जरिए आगे बढ़ने के अवसर हैं लेकिन इसी के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं जिन्हें समझें जाने की जरूरत है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भले ही भारत ने कुछ दक्षिण एशियाई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किये हैं लेकिन अब चीन उन देशों में अपनी इकाई लगाकर भारत को माल भेज रहा है जिसे रोके जाने के कूटनीतिक प्रयास करने होंगे, या फिर ऐसे मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर भी सजग रहना होगा अन्यथा भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान तय है।

बता दें कि अमेरिका द्वारा भारत पर 26

प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने से कपड़ा और परिधान, खनिज पेट्रोलियम, कृषि, मांस, प्रसंस्कृत पैकेट, प्लास्टिक सामान, मेडिकल, चमड़ा, कागज, हीरे, सोना, स्वर्ण उत्पाद, स्टील और धातु, मशीन, कम्प्यूटर, रसायन, फार्मा, इलेक्ट्रिक उत्पाद और टेलिकॉम आदि क्षेत्रों पर सर्वाधिक असर पड़ेगा, इसलिए भारत सरकार इनकी वैकल्पिक राह आसान बनाने में जुटी हुई है। उल्लेखनीय है कि दो देशों के बीच होने वाले द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के जरिए व्यापार को सुगम बनाया जाता है क्योंकि समझौते के बाद दोनों के बीच व्यापार करना आसान हो जाता है। इस तरह के समझौते के दृष्टिगत दोनों देश मिलकर अपने कारोबारियों व कम्पनियों को आयात शुल्क मुक्त या फिर एक निश्चित न्यूनतम शुल्क के जरिए वस्तुओं एवं सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित कराते हैं। इसके साथ ही लांजिस्टिक, भुगतान गारंटी व व्यापार से जुड़ी अन्य सुविधाएं मिलती हैं।

आंकड़े बताते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए को लेकर साल 2022 से लेकर अबतक 14 दौर की चर्चा संपन्न हो चुकी है जिसके बाद अब वार्ता में पुनः तेजी दृष्टिगोचर हुई है। वहीं, भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच जल्द ही एफटीए वार्ता को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। वहीं भारत और ओमान के बीच सीईपीए को लेकर आधिकारिक तौर पर वार्ता नवंबर 2023 में शुरू हुई थी, जिसके फ्रेमवर्क अब समझौता जल्द करने की तैयारी है और उसे अंतिम रूप देने की कोशिशें परवान चढ़ रही हैं। वहीं भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संघ के बीच यानी भारत, आइसलैंड, नावें, स्विट्जरलैंड, लिक्टेस्टीन के बीच एक टीईपीए समझौता हुआ है जिसे और व्यापक बनाने की पहल जारी है। वहीं, भारत और कतर के बीच एफटीए करने की बात चल रही है जिसके तहत दोनों देश अगले पांच वर्षों में अपनी व्यापार को दुगुना यानी 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता जता चुके हैं। वहीं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए प्रस्तावित है जिसको लेकर 10 वर्षों बाद फिर से बातचीत शुरू हुई है क्योंकि दोनों देश अब जल्द से

जल्द इस समझौता को पूरे करने के पक्ष में हैं। वहीं, भारत और अमेरिका के बीच भी द्विपक्षीय व्यापार समझौता को लेकर बातचीत चल रही है जिसके तहत वर्ष 2030 तक व्यापार को दुगुना करके 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

दरअसल, उपर्युक्त देशों के साथ चल रही एफटीए, सीईपीए, टीईपीए वार्ता को यदि जल्दी ही लक्षित मुकाम मिल जाता है तो दोनों देशों के बीच आयात कर (टैरिफ) कम किया जाएगा या पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, इससे व्यापार बरकरार हो जाएगा। यही नहीं, आयात की सीमाएं यानी कोटा लाइसेंस और तकनीकी नियमों को कम कर वस्तुओं और सेवाओं को सम्बन्धित दूसरे देश में बेचना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच सीमा शुल्क की प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी, कागजी काम कम होंगे और सामान को एक देश से दूसरे देश में ले जाने में समय और लागत दोनों घट जाएंगी। इसके अतिरिक्त विदेशी कम्पनियों का पैसा सुरक्षित रहता है और यदि कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाने के लिए कानूनी तरीके उपलब्ध होते हैं। वहीं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जैसी चीजों को संरक्षण मिलता है ताकि नए आविष्कार करने वालों और रचनाकारों के अधिकार सुरक्षित रहें। जबकि बैंकिंग, टेलीकॉम और पेशेवर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नियम आसान करके इनका व्यापार बढ़ाया जाता है।

सरकार उद्योगों को लांजिस्टिक सेवाएं भी उपलब्ध कराती हैं, जिससे उनके लिए यह लागत कम हो जाती है। इससे छोटी कम्पनियों और व्यापारियों को भी विदेश में सामान बेचने का मौका मिलता है, जो पहले सिर्फ बड़ी कम्पनियों तक सीमित था। यही वजह है कि सभी सरकारें दिलचस्पी वाले देशों में मुक्त व्यापार समझौतों को बढ़ावा देती हैं और द्विपक्षीय व्यापार समझौते कराती हैं। इस प्रकार दुनियावी अर्थव्यवस्था में तेजी से अपनी जगह बनाते जा रहे भारत के व्यापार के लिए विभिन्न दरवाजे स्वतः खुल जाएंगे जिससे हमारे उद्यमियों को भी ढेर सारे फायदे होंगे।

वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार



पेट्रोल-डीजल पर दो रुपये बढ़ी एक साइज ड्यूटी, जानें क्या है असली कीमत, एक लीटर पर कितना लगता है टैक्स

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर सरकार की ओर से कितना टैक्स वसूला जाता है। एक लीटर पेट्रोल की असली कीमत क्या है और आप तक पहुंचते हुए इसमें कितने रुपये तक बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश में आम आदमी के लिए पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को चलाना पहले ही महंगा है। अब सरकार की ओर से इस पर एक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक लीटर पेट्रोल-डीजल की असली कीमत

क्या है? सरकार की ओर से इस पर कितना टैक्स वसूल किया जाता है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।

100 रुपये से ज्यादा है तेल की कीमत

भारत के कई राज्यों में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से भी ज्यादा है। वहीं दिल्ली में इसकी कीमत 94-95 रुपये प्रति लीटर के बीच है। हाल में ही केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी को दो रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाया गया है। जिसके बाद यह साफ नहीं है कि एक्साइज ड्यूटी का यह भार भी आम आदमी के ऊपर पड़ेगा या नहीं।

एक साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के बाद क्या हुआ है कीमत

एक्साइज ड्यूटी में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल पर 13 और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी।

कितनी तरह का टैक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में एक

लीटर पेट्रोल पर कई तरह से टैक्स लगाया जाता है। कच्चे तेल के बेस प्राइस पर एक्साइज ड्यूटी के अलावा डीलर कमीशन और चार्ज के साथ ही वैट को भी वसूला जाता है। यह केंद्र के साथ ही राज्यों की सरकारों की ओर से भी लगाया जाता है। देशभर में कच्चे तेल की कीमत और डीलर शुल्क और एक्साइज ड्यूटी एक समान रहती है, लेकिन वैट की दर राज्यों के मुताबिक होती है। जिस कारण अलग अलग राज्यों में पेट्रोल की कीमत में अंतर होता है।

क्या है असली कीमत
देश में केंद्र और राज्यों की ओर से लगाए जाने वाले टैक्स से पहले एक लीटर पेट्रोल की कीमत 75.01 रुपये है। इसके बाद इस पर डीलर कमीशन के तौर पर 4.40 रुपये लगाए जाते हैं। अब इस पर दिल्ली में 19.4 फीसदी की दर से वैट लगाया जाता है, जो करीब 15.40 रुपये होता है। इसके बाद दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.81 रुपये हो जाती है।



पेट्रोल-डीजल पर कितना लगता है टैक्स

टाटा कर्व वर्सेज ग्रांड विटारा भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। चार मीटर से ज्यादा बड़ी एसयूवी में टाटा की ओर से कर्व को ऑफर किया जाता है। वहीं इस सेगमेंट में मारुति की ओर से ग्रेंड विटारा की बिक्री की जाती है। फीचर्स कीमत और पावर के मामले में किस एसयूवी को खरीदने में समझदारी होगी। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में किसी भी अन्य सेगमेंट के मुकाबले में एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली कारों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में मारुति की ओर से ग्रेंड विटारा और टाटा की ओर से कर्व की बिक्री की जाती है। फीचर्स, कीमत और पावर के मामले में दोनों में से किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Tata Curvv vs Maruti Grand Vitara फीचर्स

Tata Curvv में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें शॉक फिन एंटीना के साथ जीपीएस, ड्यूल टोन रूफ, ऑटो हैडलैप, इंटीग्रेटेड रियर स्पॉयलर, एलईडी डीआरएल, स्विचेशनल टर्न इंडिकेटर, वॉयस असिस्ट, पैनोरमिक सनरूफ, कर्नलिट डे लैप, 18 इंच अलॉय व्हील्स, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मूड लाइटिंग, फुली ऑटोमैटिक टैपरर



कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, जेस्टर पावर्ड टेलगेट, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, रेन सेंसिंग वाइपरस, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, हरमन ऑडियो सिस्टम, एपल कार प्ले, एंड्राइड ऑटो जैसे फीचर्स मिलते हैं।

वहीं मारुति की ओर से ग्रेंड विटारा में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जाता है। इसमें एलईडी लाइट्स, फॉलो मी हैडलैप, शॉक फिन एंटीना, एंबिएंट लाइट, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलैस चार्जर, पैडल शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, रियर एसी

वेंट, आर्किमिस साउंड सिस्टम, सुजुकी कनेक्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Tata Curvv vs Maruti Grand Vitara सेफ्टी फीचर्स

Tata की ओर से Curvv एसयूवी में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को दिया जाता है। इसमें स्टेडर्ड तौर पर छह एयरबैग को दिया गया है। जबकि सेफ्टी के लिए आई-टीपीएमएस, ट्रेक्शन कंट्रोल, थ्री पाइंट सीटबेल्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, 360 डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिफॉर्मर, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, इमोबिलाइजर, हिल

होल्ड कंट्रोल, हिल डीसेंट कंट्रोल, ईपीबी, एबीएस, इंबोडी, Level-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। वहीं मारुति ग्रेंड विटारा में सुरक्षा का भी काफी ध्यान रखा गया है। इसमें फ्रंट और कर्टेन एयरबैग, 360 डिग्री व्यू कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस, हिल होल्ड असिस्ट, इंजन इमोबिलाइजर जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

Tata Curvv Vs Maruti Grand Vitara इंजन

टाटा कर्व के पेट्रोल वेरिएंट में कंपनी की ओर से 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 120 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्पीड मैनुअल और 7डीसीए ट्रांसमिशन का विकल्प दिया जाता है।

वहीं मारुति ग्रेंड विटारा एसयूवी में कंपनी की ओर से पेट्रोल, सीएनजी और हाइब्रिड तकनीक के विकल्प के साथ इंजन को दिया जाता है। इसमें 1.5 लीटर की क्षमता का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 92.45 पीएस से लेकर 103.06 पीएस की पावर और 122 से 136.08 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ लाया जाता है और इसे एक लीटर में 19.38 किलोमीटर से 27.97 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

Tata Curvv Vs Maruti Grand Vitara कीमत

Tata Curvv ICE की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से शुरू होकर 19.20 लाख रुपये तक जाती है। वहीं मारुति की ओर से ग्रेंड विटारा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 11.19 लाख रुपये है। वहीं इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये है।

हुंडई एक्सटर Hy CNG का नया वेरिएंट EX हुआ लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री करने वाली निर्माता Hyundai की ओर से एंटी लेवल एसयूवी के तौर पर Exter की बिक्री की जाती है। एसयूवी के नए वेरिएंट को हुंडई की ओर से लॉन्च किया गया है। नए वेरिएंट के तौर पर आए EX में किस तरह के फीचर्स को दिया जाएगा। किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। साउथ कोरियाई की वाहन निर्माता Hyundai की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही एंटी लेवल एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली Exter Hy CNG को नए वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है। नए वेरिएंट में किस तरह के फीचर्स को दिया गया है। किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

हुंडई एक्सटर का नया वेरिएंट हुआ लॉन्च

हुंडई एक्सटर Hy CNG के नए वेरिएंट को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से एसयूवी के नए वेरिएंट के तौर पर EX को लॉन्च किया गया है। जिसमें कई फीचर्स को ऑफर किया गया है। इस वेरिएंट को खासतौर पर युवाओं को आकर्षित करने के लिए लॉन्च किया गया है। नए वेरिएंट को सीएनजी में बेस वेरिएंट के तौर पर ऑफर किया गया है।

कैसे होंगे फीचर्स

निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एसयूवी में कुछ फीचर्स को ऑफर किया जा रहा है। जिसमें स्टेडर्ड तौर पर छह एयरबैग, 4.2 इंच कलर्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एच-शेप एलईडी टेल लैप, ड्राइवर सीट हाइट

एडजस्टमेंट, की-लैस एंट्री जैसे फीचर्स (Hyundai Exter EX Variant features) को शामिल किया गया है।

कितना दमदार इंजन
निर्माता की ओर से एसयूवी के इंजन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.2 लीटर की क्षमता का Kappa इंजन दिया गया है। इस इंजन से एसयूवी को 69 पीएस की पावर और 95.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इसके साथ 5स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को दिया गया है।

अधिकारियों ने कही यह बात

हुंडई मोटर इंडिया के डायरेक्टर और सीओओ तरुण गंगीने कहा कि हुंडई एक्सटर हाई-सीएनजी डुओ लाइनअप में ईएक्स वेरिएंट की शुरुआत हमारे ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण का प्रमाण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि स्मार्ट मोबिलिटी व्यापक दर्शकों तक पहुंच सके। अपनी कुशल बाई-फ्यूल तकनीक, बेहतर सुरक्षा सुविधाओं और हुंडई की विश्वसनीयता के साथ, एक्सटर हाई-सीएनजी डुओ ईएक्स वेरिएंट किफायती और दक्षता का एक संतुलन प्रदान करता है।

कितनी है कीमत

हुंडई एक्सटर के नए वेरिएंट EX को भारतीय बाजार में 7.50 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च (Hyundai Exter Hy CNG EX Variant Price) किया गया है।

किनसे है मुकाबला

हुंडई की ओर से एक्सटर को एंटी लेवल एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Tata Punch, Renault Kiger, Nissan Magnite जैसी एसयूवी के साथ होता है। इसके अलावा कीमत के मामले में इसे कई हेचबैक और प्रीमियम हेचबैक कारों से भी चुनौती मिलती है।

मारुति की प्रीमियम कारों पर अप्रैल 2025 में मिल रहा लाखों रुपये की बचत का मौका, इन्वीक्टो से लेकर जिम्नी तक पर क्या है ऑफर

रिवहन विशेष न्यूज

भारत की प्रमुख वाहन निर्माता मारुति सुजुकी की ओर से Nexa डीलरशिप पर कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। इन कारों पर April 2025 में लाखों रुपये के डिस्काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं। किस कार को खरीदने पर इस महीने कितना डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति की ओर से प्रीमियम डीलरशिप Nexa के जरिए कई कारों की बिक्री की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक April 2025 के दौरान निर्माता की ओर से अपनी प्रीमियम कारों पर लाखों रुपये के डिस्काउंट ऑफर्स दिए जा रहे हैं। निर्माता किस कार पर इस महीने कितना ऑफर (Maruti Nexa Cars Offers) दे रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Ignis पर 62100 की होगी बचत
मारुति की ओर से नेक्सा डीलरशिप पर ऑफर की जाने वाली सबसे सस्ती गाड़ी Ignis पर इस महीने में 62100 रुपये के ऑफर मिल रहे हैं। यह ऑफर इसके एमटी वेरिएंट्स पर मिल रहे हैं।

Maruti Baleno पर 50 हजार रुपये तक की बचत का मौका

मारुति अपनी की प्रीमियम हेचबैक सेगमेंट में बलेनो की बिक्री की जाती है। April 2025 में इस कार पर हजारों रुपये के Discount Offers दिए जा रहे हैं। कंपनी की ओर से इस महीने में बलेनो को खरीदने पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक का फायदा उठाया जा सकता है। यह ऑफर इसके सिग्मा और एमटी वेरिएंट्स पर दिया जा रहा है। अन्य वेरिएंट्स पर कंपनी इस महीने कई ऑफर्स दे रही है।



Maruti Ciaz पर भी होगी बचत

मारुति की ओर से मिड साइज सेडान कार के तौर पर सियाज को ऑफर किया जाता है। इस कार को April 2025 में खरीदने पर अधिकतम 40 हजार रुपये के ऑफर मिल रहे हैं। यह ऑफर इसके सभी वेरिएंट्स पर मिल रहा है।

Maruti Fronx पर 45 हजार रुपये के ऑफर्स

मारुति की एसयूवी Fronx को April 2025 में खरीदना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इस एसयूवी की पर इस महीने 45 हजार रुपये तक के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। एसयूवी के टॉप वेरिएंट पर इस महीने सबसे ज्यादा बचत की जा सकती

है। वहीं एसयूवी के सीएनजी वर्जन पर केश डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस पर स्क्रीपेज और एक्सचेंज बोनस मिल रहे हैं।

Maruti Jimny पर एक लाख रुपये बचेंगे
मारुति की ऑफ रोडिंग एसयूवी के तौर पर आने वाली

जिम्नी पर भी April 2025 में लाखों रुपये के ऑफर्स दे रही है। कंपनी की ओर से इस महीने के दौरान जिम्नी पर एक लाख रुपये तक के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। यह ऑफर इसके टॉप वेरिएंट एल्फा पर मिल रहा है। इस महीने इसके बेस वेरिएंट जेटा पर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है।

Maruti Grand Vitara पर 1.35 लाख रुपये तक की बचत

मारुति की ओर से ग्रेंड विटारा एसयूवी को भी नेक्सा के जरिए ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 1.35 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। एसयूवी के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स पर यह ऑफर मिल रहा है। इसके अलावा इसके डेल्टा, जेटा और एल्फा वेरिएंट्स पर कुछ कम ऑफर्स दिए जा रहे हैं। एसयूवी के सिग्मा और सीएनजी वेरिएंट्स पर इस महीने केश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन स्क्रीपेज और एक्सचेंज डिस्काउंट्स के ऑफर मिल रहे हैं।

Maruti X16 पर 25 हजार रुपये की बचत का मौका

कंपनी की ओर से एमपीवी के तौर पर आने वाली X16 पर April 2025 में 25 हजार रुपये की छूट मिल रही है। इस गाड़ी को इस महीने खरीदने पर सिर्फ स्क्रीपेज बोनस दिया जा रहा है।

Maruti Invicto पर सबसे ज्यादा होगी बचत
मारुति की ओर से नेक्सा डीलरशिप पर सबसे प्रीमियम गाड़ी के तौर पर Maruti Invicto को ऑफर किया जाता है। इस एमपीवी पर इस महीने स्क्रीपेज बोनस और केश डिस्काउंट के साथ 1.40 लाख रुपये तक बचाए जा सकते हैं। लेकिन इसके जेटा वेरिएंट पर केश डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है।

शोरूम से मिलेगी पूरी जानकारी

अगर आपको इस महीने मारुति की किसी कार को नेक्सा डीलरशिप के जरिए खरीदना है तो डिस्काउंट ऑफर्स की पूरी जानकारी शोरूम से ही मिलेगी। अलग अलग शहर में डीलरशिप और वेरिएंट के साथ उपलब्धता के मुताबिक ही ऑफर्स को दिया जाता है।

जंगलों पर छाया इंसानों का आतंक: एक अनदेखा संकट

हाल ही में एक प्रमुख अखबार की हेडलाइन ने ध्यान खींचा—“शहर में बंदरों और कुत्तों का आतंक!” यह वाक्य पढ़ते ही एक गहरी असहजता महसूस हुई। शायद इसलिए नहीं कि खबर गलत थी, बल्कि इसलिए कि वह अधूरी थी। सवाल यह नहीं है कि जानवर शहरों में क्यों आ गए, बल्कि यह है कि वे जंगलों से क्यों चले आए? हम जिस आतंक की बात कर रहे हैं, वह वास्तव में प्रकृति का प्रतिवाद है—उस दोहरी मार का नतीजा जो हमने जंगलों और वन्यजीवों पर एक लंबे अरसे से चलाया है। विकास के नाम पर हमने जंगलों को काटा, नदियों को मोड़ा, और पहाड़ों को तोड़ा। वन्यजीवों के लिए न तो रहने की जगह छोड़ी, न भोजन का साधन। जब उनका प्राकृतिक निवास उजड़ गया, तब वे हमारी बस्तियों की ओर बढ़े। और अब, जब वे हमारी छतों, गलियों और पार्कों में दिखते हैं, तो हम उन्हें ‘आतंकी’ करार देते हैं। यह नजरिया न केवल नैतिक दृष्टि से अनुचित है, बल्कि हमारी नीति और प्राथमिकताओं में गहरी खामी को भी उजागर करता है। विकास और संरक्षण को एक-दूसरे के विरोधी खेमों में खड़ा कर देने का नतीजा यह है कि न तो सही मायनों में विकास हो पा रहा है, न ही प्रकृति का संतुलन बच पा रहा है।

प्रियंका सौरभ

हाल ही में एक अखबार की प्रमुख हेडलाइन पढ़ी—शहर में बंदरों और कुत्तों का आतंक। यह वाक्य महज एक खबर नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके का प्रतिबिंब था। हमने जानवरों के शहर में आने को आतंक करार दिया, लेकिन कभी यह सवाल नहीं पूछा कि वो शहर में आए ही क्यों? जब कोई बंदर किसी कॉलोनी की छत पर उछलता है, या कोई कुत्ता कूड़े के ढेर में भोजन तलाशता है, तो वह कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती। यह उस संकट का संकेत होता है जिसे हम—मनुष्य—ने स्वयं गढ़ा है। जंगल, जो कभी इन जीवों का घर थे, अब रियल एस्टेट की परियोजनाओं, खनन कार्यों, सड़कों और डैमों की बलि चढ़ चुके हैं। आज अगर कोई सच में आतंक फैला रहा है, तो वह है इंसानी लालच और विकास का अंधा मॉडल।

प्राकृतिक आवासों पर हमला

भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहाँ जैव विविधता की अद्भुत संपदा है। लेकिन यही भारत आज अपने ही जंगलों को खा रहा है। 2021 की Forest Survey of India रिपोर्ट बताती है कि भारत ने पिछले चार वर्षों में 1,100 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनक्षेत्र खो दिया है। हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों में यह गिरावट विशेष रूप से चिंताजनक रही है। वन कटान केवल पेड़ों का नुकसान नहीं है। यह पूरी एक पारिस्थितिकी व्यवस्था का पतन है। जब हम पेड़ काटते हैं, हम न सिर्फ ऑक्सीजन के स्रोत मिटाते हैं, बल्कि हजारों पशु-पक्षियों के घर उजाड़ देते हैं। यही कारण है

आज हमें गाँवों और शहरों के आसपास बाघ, हाथी, भालू और यहाँ तक कि तेंदुए भी दिखने लगे हैं।

शहरों में जानवरों की बढ़ती उपस्थिति: एक चेतावनी

बंदरों का शहरों में आना आज एक आम दृश्य बन गया है। दिल्ली, वाराणसी, जयपुर, और देहरादून जैसे शहरों में बंदरों की आबादी तेजी से बढ़ी है। कारण स्पष्ट हैं—कम होती हरियाली, अधिक होता कूड़ा, और बिगड़ता पारिस्थितिक संतुलन। इसी तरह, आवारा कुत्तों की संख्या भी शहरों में नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। World Health Organization के अनुसार भारत में लगभग 3.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, और हर साल हजारों लोग कुत्तों के काटने के शिकार होते हैं। मगर यह समस्या केवल स्वास्थ्य या सुरक्षा की नहीं है; यह समस्या हमारे कुप्रबंधन और लापरवाह विकास की है। हमने कूड़ा फेंकने के तरीकों को सुधारा नहीं, सार्वजनिक पशु-नियंत्रण कार्यक्रमों को प्राथमिकता नहीं दी, और अब जब जानवर हमारी बस्तियों में दिखते हैं, तो उन्हें रसंकट कर कह कर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं।

मीडिया की भूमिका और भाषा का प्रभाव

जब कोई अखबार लिखता है कि बंदरों का आतंक, तो वह केवल सूचना नहीं दे रहा होता, बल्कि एक धारणा गढ़ रहा होता है। यह धारणा कि जानवर आक्रमणकारी हैं, और हम पीड़ित। मीडिया की यही भाषा यह छिपा लेती है कि असल में हम ही उनके घरों में घुसे थे, उनकी ज़मीन छीनी, और अब जब वो अपनी जगह पाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें दोषी ठहराते



प्रतीकात्मक फोटो

हैं। यह भाषा केवल संवेदनहीन नहीं, बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि इससे संरक्षण के प्रति समाज की समझ और सहानुभूति दोनों कमजोर पड़ती हैं।

वन्यजीव संघर्ष: क्यों बढ़ रहा है?

एकरिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल औसतन 100 से अधिक लोग हाथियों के घटनाओं में मारे जाते हैं, और दर्जनों बाघ-मानव संघर्षों की घटनाएँ सामने आती हैं। मगर इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई यह है कि वन्यजीवों का घर सिकुड़ता जा रहा है। जंगलों में भोजन और पानी की कमी उन्हें मानव बस्तियों की ओर

खींचती है। कभी-कभी वे रास्ता भटक जाते हैं, तो कभी उन्हें मजबूरी में खेतों और घरों में घुसना पड़ता है। यह संघर्ष उनके लिए भी घातक है—हर साल सैकड़ों जानवर इंसानी जवाबी हिंसा में मारे जाते हैं।

क्या हो सकता है समाधान?

भारत में Wildlife Protection Act 1972 और Forest Conservation Act 1980 जैसे सशक्त कानून हैं, लेकिन उनके लागू करने में अनेक समस्याएँ हैं। वन विभाग अक्सर संसाधनों और जनबल की कमी से जूझता है। इसके अलावा, जब

विकास परियोजनाओं और वन्यजीव संरक्षण में टकराव होता है, तो अक्सर विकास को तरजीह दी जाती है, भले ही उसके दीर्घकालिक परिणाम विनाशकारी हों। इस संकट से उबरने के लिए केवल नीतियाँ नहीं, बल्कि सोच का परिवर्तन जरूरी है। कुछ संभावित उपाय इस प्रकार हैं: शहरी नियोजन में हरित क्षेत्र सुनिश्चित किया जाए—पाक, बाग-बगिचे, और वृक्षारोपण को केवल सजावटी पहलू नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी के हिस्से के रूप में देखा जाए। वन्यजीव गलियारों (wildlife corridors)

विकसित किए जाएँ—जिससे जानवरों को सुरक्षित आवागमन का रास्ता मिले। कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए—ताकि जानवर शहरी कूड़े पर निर्भर न हों। मीडिया और शिक्षा में संवेदनशीलता लाई जाए—जानवरों को ‘आतंकवादी’ बताने के बजाय उनके संघर्ष को समझने और सहानुभूति की भाषा अपनाई जाए। स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाए—उन्हें संरक्षण के साझेदार बनाना होगा, विरोधी नहीं।

अंतिम बात: इंसान अकेला नहीं है इस धरती पर

हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह धरती केवल हमारी नहीं है। जंगलों, नदियों, पहाड़ों, और समुद्रों के साथ-साथ हर जीव-जंतु का इस पर अपना ही अधिकार है जितना हमारा। जब हम शहरों का विस्तार करते हैं, जब हम मॉल और एक्सप्रेसवे बनाते हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी न किसी की ज़मीन छीनी जा रही है—कभी किसी हिरन की, कभी किसी हाथी की। हम अगर प्रकृति से लड़ते रहेंगे, तो अंततः हार हमारी ही होगी—क्योंकि प्रकृति को हराया नहीं जा सकता, बस अस्थायी रूप से दबाया जा सकता है। इबंदरों का आतंक एक समाचार की हेडलाइन हो सकती है, लेकिन असल हेडलाइन यह होनी चाहिए थी—हम जंगलों पर इंसानों का आतंक। इस सच्चाई को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन जरूरी है। अगर हम वास्तव में एक संतुलित, सुरक्षित और संवेदनशील समाज की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति से नहीं, अपने अहंकार से संघर्ष करना होगा।

यमराज का दूसरा नाम धर्मराज क्यों?

प्राणी की मृत्यु या अंत को लाने वाले देवता यम हैं। यमलोक के स्वामी होने के कारण ये यमराज कहलाए। चूंकि मृत्यु से सब डरते हैं, इसलिए यमराज से भी सब डरने लगे जीवित प्राणी का जब अपना काम पूरा हो जाता है, तब मृत्यु के समय शरीर में से प्राण खींच लिए जाते हैं, ताकि प्राणी फिर नया शरीर प्राप्त कर नए सिरे से जीवन प्रारंभ कर सके। यमराज सूर्य के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम संज्ञा है। उनका वाहन भैंसा और संदेशवाहक पक्षी कबूतर, उल्लू और कौबा भी माना जाता है। उनका अचूक हथियार गदा है। यमराज अपने हाथ के कालसूत्र या कालपाश की बंदीतल जीव के शरीर से प्राण निकाल लेते हैं। यमपुरी यमराज की नगरी है, जिसके दो महाभयंकर चार आँखों वाले कुत्ते पहरेदार हैं। यमराज अपने सिंहासन पर न्यायमूर्ति की तरह बैठकर विचार भवन कालीची में मृतात्माओं को एक-एक कर बुलावते हैं, जहाँ चित्रगुप्त सब प्राणियों की बही खोलकर लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं। कर्मों को ध्यान में रखकर यमराज अपना फैसला देते हैं, क्योंकि वे जीवों के शुभाशुभ कर्मों के निर्णायक हैं।

यमराज की यूँ तो कई पत्नियाँ थीं, लेकिन उनमें सुशीला, विजया और हेमना अधिक जानी जाती हैं। उनके पुत्रों में धर्मराज युधिष्ठिर को सभी जानते हैं। न्याय के पक्ष में फैसला देने के गुणों के कारण ही यमराज और युधिष्ठिर अक्सर दोनों धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं। यम द्वितीया के अवसर पर जिस दिन भाई-बहन का त्योहार भैया-दूज मनाया जाता है। यम और यमुना की पूजा का विधान बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि यमुना नदी को यमराज की बहन माना जाता है। भौमवारी चतुर्दशी को यमतीर्थ के दर्शन कर सब पापों से छुटकारा मिल जाए, उसके लिए प्राचीन काल में यमराज ने यमतीर्थ में (संकटाघाट) कठोर तपस्या करके भक्तों को सिद्धि



प्रदान करने वाले यमेश्वर और यमादित्य मंदिरों की स्थापना की थी। यम द्वितीया को यहाँ मेला लगता है। इन मंदिरों को प्रणाम करने वाले एवं यमतीर्थ में स्नान करने वाले मनुष्यों को नारकीय यातनाओं को न तो भोगना पड़ता है और न ही यमलोक देखना पड़ता है। इसके अलावा मान्यता तो यहाँ तक है कि यमतीर्थ में श्राद्ध करके, यमेश्वर 1. का पूजन करने और यमादित्य को प्रणाम करके व्यक्ति अपने पितृ-ऋणा से भी उच्छ्रा हो सकता है।

श्राद्ध कृत्या यमे तीर्थे पूजयित्वा यमेश्वरम्- यमादित्यं नमस्कृत्य पितृणामनुगो भवेत्।

दीपावली से पूर्व दिन यमदीप दैकर तथा दूसरे पर्वों पर यमराज की आराधना करके मृत्यु उनकी कृपा प्राप्त करने के उपाय करता है। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि किसी समय माण्डव ऋषि ने कुपित होकर यमराज को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का शाप दिया। इसके कारण यमराज ने ही दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र तथा पाण्डु के भाई होकर जन्म लिया। यूँ तो यमराज परम धार्मिक और भगवद् भक्त हैं। मृत्यु जन्म लेकर भी वे भगवान् के परम भक्त तथा धर्म-परायण ही बने रहे।

यमराज की मृत्यु कैसे हुई?

यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है यदि यमराज स्वयं मृत्यु के देवता हैं तो इनकी मृत्यु कैसे संभव है? यह बात हास्यप्रद सी लगती है परंतु वेद और पुराण में इनकी मृत्यु की एक कथा बताई गई है। इसको बताने से पहले यमराज के बारे में कुछ जान लेना बहुत जरूरी है। यमराज की एक जुड़वा बहन थी जिसे यमुना भी कहा जाता है। यमराज भैसे की सवारी करते हैं और यमराज की आराधना विभिन्न नामों से की जाती है जैसे कि यम, धर्मराज मृत्यु, आतंक, वैवस्वत और काल। बहुत समय पहले एक श्वेत मुनि थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे और गोदावरी नदी के तट पर निवास करते थे जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यम देव ने उनके प्राण लेने के लिए मृत्यु पास को भेजा लेकिन श्वेतमुनि अभी पुराण नहीं त्यागना चाहते थे तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जब मृत्यु पास श्वेत मुनि के आश्रम में पहुँचे तो देखा कि आश्रम के बाहर भैरो बाबा पहरा दे रहे हैं। धर्म और दायित्व में बंधे होने के कारण जैसे ही मृत्यु पास ने मुनि के प्राण हरने की कोशिश की तो भैरव बाबा ने प्रहार करके मृत्यु पास को मुर्छित कर दिया, वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई यह देखकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और स्वयं आकर भैरव बाबा को मृत्युपाश में बांध लिया फिर श्वेत मुनि के प्राण हरने के लिए उन पर भी मृत्युपाश डाला पर श्वेत मुनि ने अपने इष्टदेव महादेव को पुकारा और महादेव ने तुरंत अपने पुत्र कार्तिकेय को भेजा। कार्तिकेय के पहुंचने पर कार्तिकेय और यम देव के बीच घमासान युद्ध हुआ, कार्तिकेय के सामने यमराज टिक नहीं पाए और कार्तिकेय के प्रहार से जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य को जब यमराज की मृत्यु का समाचार लगा तो वह विचलित हो गए, ध्यान लगाने पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के विपरीत श्वेत मुनि के प्राण हरने चाहे थे इस कारण यमराज को भगवान भोले के क्रोध को झेलना पड़ा। यमराज सूर्य देव के पुत्र हैं और इस समस्या के समाधान के लिए सूर्य देव भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्य देव ने भगवान शिव की चार तपस्या की जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा तब सूर्य देव ने कहा कि “हे महादेव, यमराज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भारी अस्तंतुलन फैला हुआ है, पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनर्जीवित कर दें” भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर छिड़का जिससे वो पुनः जीवित हो गए...!!

आपसी संवाद, जनता की जगरूकता से खत्म होगा नक्सलवाद!

हाल ही में 5 अप्रैल 2025 को दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम महोत्सव में समापन समारोह के दौरान हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने यह बात कही है कि अगली चैन नगरात्रि चक्र बस्तर से लाल आकासमाप्त हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने बस्तर की खुशहाली की कामना की। पाठकों को बताता चलू कि उन्होंने-उन्होंने कहा कि 'बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। नक्सलियों से अपील है कि वे आत्मसमर्पण करें। नक्सलियों को सरेंडर कराकर गांवों को नक्सल मुक्त कराइये। हर गांव को एक करोड़ मिलेगा।' कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि 'बस्तर पंडुम को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने के लिए एन।यू।आर के राजदूत जो राजधानी में हैं, उनको बस्तर में दुनिया हमारी परंपराओं को, संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम सरकार करेगी।' वास्तव में, गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से यह कहा है कि 'आप सब हमारे अपने हैं और आप हथियार डाल कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों। जब कोई नक्सली मारा जाता है, तो कोई भी खुश नहीं होता।' बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि आज नक्सलवाद हमारे देश और समाज के लिए एक बड़ी समस्या है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्च, 2026 तक नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नक्सलमुक्त घोषित गांवों को एक करोड़ रुपये की विकास निधि देने तथा नक्सलियों की सुरक्षा और पुनर्वास को व्यवस्थापन सरकार द्वारा सुनिश्चित करने की बात यह स्पष्ट दर्शाती है कि सरकार विकास को वजन देकर नक्सलवाद को खत्म करने की ओर लगातार अग्रसर है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ समय पहले ही मार्च के अंतिम सप्ताह में ही छत्तीसगढ़ में 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, उसके बाद सुरक्षाबलों ने एक साथ 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार कुल दो जगहों से नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। जिले के उसुर थाना क्षेत्र के टेकमेटेला गांव के पास जंगल से सात नक्सलियों को पकड़ा गया, जबकि बासगुड़ा थाना क्षेत्र से छह नक्सलियों को पकड़ा गया था। यहां गंभी उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया

प्लेटफॉर्म पर एक एक्स पोस्ट में यह बात कही थी कि, 'नक्सलवाद पर एक और प्रहार! हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान के दौरान 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया और स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता; केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है।' वास्तव में नक्सलवाद का समूह नाश करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कितनी अच्छी बात है कि आज सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा के समाज में वापस लौटने में सहायता के लिये वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक पुनर्एकीकरण कार्यक्रम प्रदान कर रही है। यदि हम यहां आंकड़ों की बात करें तो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 126 (वर्ष 2014) से घटकर मात्र 12 (वर्ष 2024) रह गई है। आंकड़े बताते हैं कि नक्सल-संबंधी घटनाएँ 16,463 (वर्ष 2004-2014) से घटकर 7,700 (वर्ष 2014-2024) हो गई हैं तथा नक्सलवाद के कारण सुरक्षा बलों की हताहतों की संख्या में 73% की कमी आई है, जबकि नागरिक हताहतों की संख्या में 70% की कमी आई है। बहरहाल, पाठकों को बताता चलू कि नक्सलवाद, माओवादी विचारधारा से प्रेरित वामपंथी उग्रवाद का एक रूप है, जो सशस्त्र विद्रोह (हिंसा और गुरिल्ला युद्ध) के माध्यम से राज्य को समाप्त करने का प्रयास करता है। यदि हम नक्सलवाद की उत्पत्ति की बात करें तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई है, जहाँ वर्ष 1967 में शोषक जमींदारों के खिलाफ किसानों का विद्रोह हुआ था। नक्सलवाद के कारणों की बात करें तो यह असमान भूमि वितरण और जमींदारों, साहूकारों एवं विचौलियों द्वारा शोषणकारी प्रथाओं के कारण बढ़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी कहीं न कहीं नक्सलवाद का कारण बना। नक्सलवाद के पीछे जनजातीय अलगाव भी एक प्रमुख कारण रहा है। इतना ही नहीं, सरकारी तंत्र



अनुपस्थिति, बुनियादी सेवाओं की कमी, तथा हिरासत में मृत्यु सहित पुलिस की ज्यादतियों के मामलों ने शिकायतों को और बढ़ा दिया है, जिससे नक्सली विद्रोह को मजबूती मिली। पाठकों को बताता चलू कि माओवाद का आदर्श वाक्य, 'शक्ति बंदूक की नली से निकलती है' रहा है। बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि आज सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक असमानता को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सलवा जूझ की शुरुआत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2005 में माओवादियों के खिलाफ सरकार द्वारा समर्थित 'लोगों के प्रतिरोध आंदोलन' के रूप में हुई थी। यहां पाठकों को बताता चलू कि दंतेवाड़ा और बस्तर के आदिवासियों की गोंडी भाषा में, सलवा जुडूम का

मल्लव शांति मार्च होता है। लेकिन असल में, इसमें माओवादियों से लड़ने के लिए अधिकारियों द्वारा आदिवासी ग्रामीणों को हथियार दिए गए थे। बहरहाल, गौरतलब है कि श्री शाह के बस्तर प्रवास के दरम्यान छत्तीसगढ़ के 86 नक्सलियों ने हैदराबाद में सामूहिक समर्पण किया है, जिनमें बीस नक्सल महिलाएं भी शामिल हैं। ऊपर जानकारी दे चुका हूँ कि पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से वर्ष 1967 में शुरू किसानों के विद्रोह को नक्सलवाद कहा गया था और इसमें शामिल लोगों को नक्सलवादी या नक्सल कहा जाने लगा। कहना गलत नहीं होगा कि वास्तव में इनको मुख्यतया वामपंथी आंदोलनों से जोड़ा जाता रहा है, जो कि माओवादी राजनीतिक विचारधारा का पालन करते हैं। यहां पाठकों को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि सरकार के अनुसार देश में नक्सल प्रभावित जिले सत्रह से घट कर छह रह गए हैं और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और ओडिशा में इनकी (नक्सलवाद) की जड़ें फैली हुई हैं। गौरतलब है कि बिहार के दो जिले बांका और पश्चिमी चंपारण (बागहा) को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। अब राज्य के आठ जिले ही नक्सल (नक्सलवाद) प्रभाव वाले रह गए हैं, जिनमें क्रमशः

औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय और रोहतास शामिल हैं। पाठकों को बताता चलू कि गया का इमामगंज बिहार का अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था। दरअसल, नक्सली समय-समय पर सरकार के प्रति नाराजगी और बुनियादी जरूरतों की विभिन्न मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन करते रहे हैं। बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि नक्सलवाद आज धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है और आने वाले समय में देश इस समस्या से छुटकारा पा लेगा। कहना गलत नहीं होगा कि नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देकर विकास को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहना गलत नहीं होगा कि नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ शिक्षित और सक्षम हो सकें। इतना ही नहीं, जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के साथ ही साथ उनके साथ संवाद (बातचीत का रास्ता) स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही, सुरक्षा बलों को सुदृढ़ शैल्युपस्थिति देना चाहिए। नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए नक्सलवाद पर स्थायी नियंत्रण संभव है। हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन आवश्यक है। नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना अति आवश्यक है। रोजगार के अवसर बढ़ें और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण होगा तो कोई दुराग्र नहीं कि नक्सलवाद की समस्या पर लगाम नहीं लगाई जा सके। नक्सलियों का पुनर्वास, भूमि सुधार और सामूहिक प्रयास भी जरूरी है। गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी प्रमुख हथियार तो नक्सलवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं नक्सलियों को स्थानीय मदद को रोकने के लिए कट्टर उठाए जाने चाहिए। सबसे बड़ी बात नक्सली घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही जनता को भी जागरूक होना होगा।

सुनील कुमार महला, प्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।



हीटवेव: भारत के लिए बढ़ता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट

भारत में हीटवेव अब केवल मौसमी असुविधा नहीं, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुकी है। वर्ष 2024 में हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता रिकॉर्ड स्तर पर पहुँची, विशेषकर उत्तर-पश्चिम भारत में। अत्यधिक तापमान के कारण डिहाईड्रेशन, हीट स्ट्रोक, श्वसन व हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि हुई है, जिससे बुजुर्गों, बच्चों, निम्न आय वर्ग और बाहरी श्रमिकों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ा है। शहरी ताप द्वीप प्रभाव, जल संकट, बिजली कटौती और कार्य उत्पादकता में गिरावट जैसे मुद्दे स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। श्रमिकों और महिलाओं को भारी गर्मी में काम करना पड़ता है जिससे स्वास्थ्य और आजीविका दोनों पर असर पड़ता है।

डॉ० सत्यवान सौरभ

गर्मी का मौसम भारत में नया नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी प्रकृति खतरनाक होती जा रही है। कभी मौसमी बदलाव माने जाने वाली हीटवेव अब हमारे शहरों और गांवों में एक नियमित आपदा का रूप ले चुकी है। वर्ष 2024 में उत्तर-पश्चिम भारत में 181 हीटवेव दिन दर्ज किए गए — जो अब तक का सबसे ऊँचा आँकड़ा है। यह संख्या केवल मौसम के आंकड़े नहीं हैं; यह जीवन, स्वास्थ्य और आजीविका पर मंडराते खतरों की स्पष्ट चेतावनी है। हीटवेव, सामान्य तापमान सीमा से अधिक अत्यधिक गर्मी की लंबी अवधि है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में और भी भूषण हो गई है। वर्ष 2024 में भारत में कई राज्यों में 554 हीटवेव के दिन दर्ज किए जिसमें अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। इस वृद्धि ने गर्मी से संबंधित बीमारियों को बढ़ा दिया है, जो

बुजुर्गों, मजदूरों और कम आय वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित कर रहा है। हीटवेव और स्वास्थ्य: छाया की कमी, संकट की अधिकता अत्यधिक गर्मी का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डिहाईड्रेशन, हीट-स्ट्रोक, हृदयगतिकी का तेज हो जाना, और सांस लेने में तकलीफ — ये सब हीटवेव के साथ आने वाली आम समस्याएँ हैं। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। झारखंड में इस साल बाल चिकित्सा वार्ड में डिहाईड्रेशन के मामलों में असामान्य वृद्धि दर्ज की गई। तेज शहरीकरण और हरियाली की कटौती ने शहरों को ताप द्वीप में बदल दिया है। दिल्ली जैसे शहरों में रात का तापमान भी सामान्य से 4-5 डिग्री अधिक बना रहता है। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के लिए यह स्थिति कष्टदायक से जानलेवा तक हो सकती है। हीटवेव और जीवन व्यवस्था पर असर गर्मी के कारण स्कूल बंद होते हैं, पानी की सप्लाई बाधित होती है, बिजली कटौती आम हो जाती है। गरीब और मेहनतकश वर्ग, जिनके पास न ठंडी जगह होती है, न संसाधन, सबसे अधिक संकट में होते हैं। हीटवेव केवल सेहत का नहीं, आर्थिक उत्पादन का भी सवाल बन गई है। निर्माण श्रमिक, किसान और सड़क विक्रेता जैसी बाहरी कामकाज से जुड़े लोगों की उत्पादकता गिर रही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, हीटवेव के कारण भारत में कार्य घंटों में 2.2% की गिरावट आ सकती है, जो GDP में 2.8% तक की हानि बन सकती है। सब पर असर एक जैसा नहीं होता हीटवेव की मार सभी पर एक समान नहीं होती। जिनके पास एयर कंडीशनर, स्वच्छ जल और स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं हैं, वे अधिक

सुभेद्य होते हैं। ग्रामीण महिलाएँ जो जल लाने या खेतों में काम करती हैं, उन्हें दोगुना खतरा होता है। शहरों के गरीब बस्तियों में रहने वाले परिवारों के लिए हीटवेव असमानता का सबसे तेज रूप बन जाती है। हीटवेव से लड़ाई सिर्फ एक मौसमीय अलर्ट से नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, शहरी नियोजन, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार और सामुदायिक भागीदारी जरूरी है। अहमदाबाद, सूरत और भुवनेश्वर जैसे शहरों ने हीट एक्शन प्लान अपनाकर यह दिखाया है कि नियोजित प्रयासों से मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। सूरत में 'कूल रूफ' योजना ने झुग्गियों में तापमान को 3-4 डिग्री कम किया। भुवनेश्वर में भीड़ वाले बाजारों में पेयजल स्टॉल और छाया ढांचे लगाए गए। हीट गवर्नंस: अब जरूरत है कानूनी और नीतिगत ढाँचे की सटीक ताप पूर्वानुमान और सार्वजनिक चेतावनियाँ स्वास्थ्य जेम्बिंको को कम करने में मदद करती हैं। अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान (2013) ने कूलर-कोडेड अलर्ट पेश किए जिससे निवासियों और अस्पतालों को अत्यधिक तापमान वाली स्थिति के लिए तैयार होने में मदद मिली। अस्पतालों में कूलिंग स्पेस बनाना, स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करना और पर्याप्त चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करना गर्मी से संबंधित मृत्यु दर को कम कर सकता है। ठाणे में हीटस्ट्रोक के मामलों पर नजर रखने और तत्काल चिकित्सा मध्यक्ष प्रदान करने के लिए रियलटाइम निगरानी शामिल है। कूलिंग सेन्टर्स बनाना, ओएस पैकेज वितरित करना, और जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, निम्न आय वाले समुदायों की सुरक्षा में मदद करता है। भुवनेश्वर में गर्मी से होने वाली थकावट को रोकने के लिए भीड़भाड़ वाले बाजारों में अस्थायी छाया संरचनाएँ और जलयोजन स्टेशन

स्थापित किए गए थे। हरित आवरण का विस्तार, रिफ्लेक्टिव रूफ्स को बढ़ावा देना, और जलाशयों का निर्माण करके शहरी तापमान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सूरत ने झुग्गी-झोपड़ियों में कूल-रूफ पहल शुरू की, जिससे घर के अंदर का तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, जिससे हजारों निवासियों को लाभ हुआ। जिस तरह दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के लिए GRAP (Graded Response Action Plan) लागू होता है, वैसे ही हीटवेव के लिए भी स्वचालित, डेटा-आधारित नीति ढाँचे की जरूरत है। भविष्य की गर्मी से मुकाबला आज की नीति से हीटवेव केवल गर्मी नहीं है, यह एक चेतावनी है — हमारे शहरों की संरचना, हमारी आर्थिक नीतियों और हमारे स्वास्थ्य सिस्टम की परीक्षा। भारत को अब हीटवेव को 'प्राकृतिक आपदा' मानकर, उसके अनुसार तैयारी करनी होगी। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चिंता नहीं है — यह वर्तमान की हकीकत है। और इस हकीकत से लड़ने के लिए हमें चाहिए नीति, नवाचार और न्याय। तभी हम उस गर्म भविष्य को थोड़ा और सहनीय बना सकेंगे, और शायद थोड़ा ठंडा भी। हीटवेव के बढ़ते खतरों को कम करने के लिए हीट हेल्थ गवर्नंस को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। एक सक्रिय दृष्टिकोण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, शहरी ताप कार्रवाई योजनाओं, प्रत्यास्थ बुनियादी ढाँचे और सामुदायिक भागीदारी को एकीकृत करके जीवन की रक्षा की जा सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण बुनियादी ढाँचे और सामुदायिक सहयोगात्मक नीति निर्माण, वैज्ञानिक नवाचार और संधारणीय शहरी नियोजन के माध्यम से दीर्घकालिक प्रत्यास्थता का निर्माण किया जा सकता है।

पुलिस यूनियन ने बीजेपी बरिष्ठ बिधायक जयनारायण मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर : राज्य पुलिस एसोसिएशन ने भाजपा विधायक जयनारायण मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। संघ के कार्यकारी सचिव उमेश चंद्र साहू ने कहा कि संघ ने जयनारायण द्वारा पुलिस अधिकारी को धमकाने की घटना की निंदा की है और कहा है कि इस घटना के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायक का ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है। अगर ऐसा हुआ तो जनता के मन में

कानून का कोई डर नहीं रहेगा। विधायक की धमकियाँ शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यूनियन ने डीजीपी से मांग की है। हम इंतजार कर रहे हैं कि डीजीपी क्या कदम उठाते हैं। डीजीपी की पहल के आधार पर यूनियन आगे का निर्णय लेगी। दूसरी ओर, बरिष्ठ कांग्रेस नेता सुर राउतराय ने जयनारायण की धमकी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, जय नारायण मंत्री न बन पाने से व्यथित हैं। हालाँकि, इस मुद्दे पर जयनारायण की राय नहीं मिल सकती।



ढेंकानाल में बरा दिवस बड़ी धूमधाम से पलित हुआ



मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा
भुवनेश्वर : 7 अप्रैल बरा दिवस है। ढेंकानाल जिला अपने बरा के लिए प्रसिद्ध है। लोकेशन यह ढेंकानाल बरा अब सभी जिलों में फैल गया है। रिडन सिटी की सभी बाहरी की दुकानों पर परला भोजन। यहाँ तक कि हर घर में टिन के डिब्बों ने अपनी जगह ले ली है। शादी की तैयारी करना इतना शुभिकल नहीं है। इसे बीजों को पीसकर और उसमें थोड़ी सूजी मिलाकर तैयार किया जाता है। कुछ लोग बीरा बाटम में चावल भी मिलाते हैं। नक्खन पिछले के बाद, व्याज, निर्व और अदरक को मिलाकर अधिक स्वादिष्ट घोल तैयार किया जाता है। बरा का स्थान रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों की सूची में है। सालों, बरा की पर्याय ढेंकानाल से है। बरा इस जिले में 150 वर्षों से अधिक समय से प्रसिद्ध है। ढेंकानाल शहर में छोटे से लेकर बड़े होटलों तक विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के बरा तैयार किए जाते हैं। लोग बाहरी से लेकर शाम तक बरा का आनंद लेते हैं। सालों, जैरा और अदरक मिलाकर बनाए गए बरा का स्वाद निर्यात बरा से थोड़ा अलग होता है। अभी भी इस उत्पाद की मांग बहुत अधिक है। इससे वे केवल भोजन उपलब्ध हुआ है, बल्कि कई लोगों को अच्छा रोजगार भी मिला है। आज बरा दिवस पर सभी ने जगह-जगह बरा खाकर इस दिन को मनाया।

केंद्रीय गृह सचिव पोस्टो-अफीम खेती, विपणन पर भी जायजा लेगे ?

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

रांची, केंद्रीय गृहसचिव कल झारखंड आयेगे वे पदाधिकारी का अवैध व्यापार रोकने के लिए किये गये विशेष पहल और जागरूकता अभियान सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए झारखंड गृह विभाग की ओर से सभी जिलों के डीसी और एसपी को पत्र लिखा गया है।



पत्र में बताया गया है कि जिला स्तर पर मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को लेकर की गयी कार्रवाई पर परिचर्चा की जायेगी, इसके लिए जिला स्तर पर एक जनवरी 2024 से लेकर अभी तक की गयी कार्रवाई के संबंध में गृह विभाग ने रिपोर्ट मंगी है। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2024-25 में पुलिस ने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती को नष्ट करने की कार्रवाई की, 2025 में फरवरी माह तक करीब 20 हजार एकड़ में अफीम की फसल नष्ट की गयी। लेकिन पिछले चार वर्षों के दौरान की गयी

खरसावां जिले में जंगलों से बड़े पैमाने पर 70 चोरी की मोटरसाइकिल अगर बरामद की जाती एवं कुछ गांव में अचानक खपडेल के मकान पक्के बन जाते हैं वे तो साधारण व्यापारी हैं पर मिडिल मैन जो राष्ट्रीय - अन्तर्राष्ट्रीय पैडलरों को जोड़ देता तो क्यों विपणन कारी के पास पुलिस नहीं पहुँच पाई आज तक ? संबंधित पुलिस थानों की भूमिका कैसी रही

होगी क्या इसकी जानकारी भी केंद्रीय गृह सचिव लेंगे ? सबसे बड़ी बात विगत कुछ वर्षों से आदिवासी इलाका नाकीटिक पदाधिकार का झारखंड में सर्वाधिक चर्चित स्थल रहा है। जिसे स्वयं केन्द्रीय गृह मंत्री इस दिशा में सख्त है एवं संबंधित केन्द्रीय विभागों को भी पता है तो सचिव को भी जानकारी हो सकती है !

विश्वप्रसिद्ध सरायकेला छऊ आध्यात्मिक पूजन के साथ आरंभ



कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

सरायकेला। विश्वप्रसिद्ध सरायकेला छऊ नृत्य आयोजन पूर्व आध्यात्मिक अनुष्ठान अखाड़ा साल पूर्व दिशा श्मशान समीप भैरव पूजन में आज शाम पवित्र शुभघट का आगमन हुआ। वैसाख मास आरंभ ओड़िया नव वर्ष हेतु यथा बार-नक्षत्र, ऋतु, दिन, सभी तिथियों, राशियों का पूजन ओड़िया जनमानस नववर्ष संक्रांति जिसे जगन्नाथ संस्कृति में पणा संक्रांति कहा जाता उस निमित्त चार युगों को प्रदर्शित करता चार घंटे शेष दिन का का शुभारंभ पूजन आरंभ हुआ। रविवार को विधिवत पूर्व दिशा अखाड़ा साल में भैरव जी का पूजन संपन्न हुआ। जहाँ कार्यकारी एस डी ओ सरायकेला निवेदिता नियती तथा सत्येन्द्र कुमार उपस्थित रहे तथा सत्येन्द्र कुमार पूजन कर्ता के



रूप में पूजा अर्चना की। यह पूजन एक सांकेतिक उत्सव होता है ओड़िया पाइक संस्कृति का। जब कलिंग की पाइक सेनाएँ अपने खंडायत सैन्य नायकों के अगुवाई में युद्ध में जाया करते थे तब अपने तलवारों में शत्रुओं को समन करने हेतु इन्ही श्मशान में तलवारों में भैरव-भैरवी आदि उग्र देवता को स्थान देने हुए आवाहन किया करते थे। आज युद्ध तो नहीं होते पर कभी यहाँ की तलवारों की पूजन सदैव विदेशों में चर्चित रहा। आज से तीन दशक पूर्व तक अनेक देश, एम्बेसी, मंत्रालय समेत प्रधानमंत्री गण भी नृत्य के साथ इन पूजन के विषय में जानने हेतु लालायित रहते थे। तब सरायकेला कला के मामले में सुखियों में होता था। इधर सोमवार शाम माँजा घाट से छऊ आरंभ हो कर शुभघट का आगमन के साथ लोगों ने दर्शन किया। यह आगामी चार घंटों एवं वर्ष का शुभारंभ का प्रतीक है।



कोरेमुला स्थित सीरवी समाज मंदिर (बडेर) के तवावधान में आयोजित चैत्र नवरात्रि महोत्सव के तहत रविवार को हवन का आयोजन किया गया। शुभ मुहूर्त में पूजा-अर्चना कर श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार के साथ हवन में पूर्णाहुति दी। अवसर पर उपस्थित अध्यक्ष कालुराम काग, पौकरराम काग, राजुराम लचेटा, नगाराम काग, महिला मंडल कंचन देवी काग, विमला देवी लचेटा, भीकी देवी काग सुनीता काग व पंडित बाबूलाल शर्मा आदि उपस्थित रहे।



गाजुलारामस्थित भोलेनाथ गुप्त द्वारा श्रीराम नवमी गाजुलारामसर्कल के समीप छाछ का वितरण किया गया, जिसमें भोलाराम गेहलोत, सेसाराम पंवार, मंगलराम पंवार, बंशीलाल प्रजापति, हरिसिंह राठौड़, दुर्गाराम मुलेवा, अशोक हाबड, भुराराम सैणवा, ओमकाश सैणवा, धर्माराम माली, जोराराम सोलंकी, मोहनलाल बर्फा, सेसाराम परिहारिया, दिनेश सेपटा का विशेष सहयोग रहा। अवसर पर भोलेनाथ गुप्त व अन्य उपस्थित थे।

आत्म-रक्षा के संस्कार दीजिए...!

कन्याओं को ऐसे ही न पुजिए। आत्म-रक्षा के संस्कार दीजिए। बेटीना साथ हो कभी छेड़छाड़, चेतना जगाने की ले लो आड। शिक्षा का स्तर बढ़ा यू बढ़ाओ, न हो यौन शोषण साथ आओ।

कन्याओं को ऐसे ही न पुजिए। आत्म-रक्षा के संस्कार दीजिए। खूब निमाओ, वस्त्रादि दो धेट, मानसिक व शारीरिक करों सेट। कराओ अवगत उन्हें गुड-बेडटच, पापी व बलात्कारी न जाये बच।

कन्याओं को ऐसे ही न पुजिए। आत्म-रक्षा के संस्कार दीजिए। कन्याओं में ऐसी शक्ति जगाएँ, अधर्मी चाहकर भी छू ना पाएँ। पेरेंट्स पुत्रों को ये सबक सिखाएँ, शीलभंग का उन्हें भी डर बैठ जाएँ।

संजय एम तराणेकर

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18, 19, 20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, ग्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023

